नेपाल के राजनीतिक आन्दोलन में मधेसी समुदाय का योगदान

राणा, राजा से गणतन्त्र तक

जय प्रकाश गुप्ता

नेपाल के राजनीतिक आन्दोलन में
मधेसी समुदाय का योगदान

राणा-राजा से गणतन्त्र तक

लेखक
जय प्रकाश गुप्ता

इस पुस्तिका प्रकाशन का उद्देश्य

इसे पढने से आप को ज्ञात होगा कि नेपाल मे राणाशाही से मुक्ति की आन्दोलन, संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली के स्थापना का संघर्ष, राजा के द्वारा लगाये गए पंचायति तानाशाही के बिरुद्ध का लडाई से होते हुए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना की कठिन यात्रा के दौरान-हरेक मोर्चाओं मे मधेसी समुदाय ने बलिदान दिया हैं । मधेसी समुदाय के बलिदान के बगैर नेपाल मे कोई भी परिवर्तन संभव नही था । परन्तु हरेक परिवर्तन के बाद मधेसी समुदाय के राजनीतिक मांगों को राज्य के द्वारा तिरस्कार किया गया । साथ हि, मधेसी समुदाय के द्वारा स्थापित राजनीतिक पार्टीओं का एक संक्षिप्त लेखाजोखा भी इस पुस्तिका मे किया गया हैं । फिर भविष्य का रास्ता क्या हैं ? यह बताने का कोशिस किया गया हैं । आशा हैं, इतिहास से आप वाकिफ होगें ।

नेपाल के राजनीतिक आन्दोलन मे मधेसी समुदाय का योगदान

राणा-राजा से गणतन्त्र तक

नेपाल की शासन व्यवस्था को प्रजातान्त्रिकरण करने मे मधेसी समुदाय का ऐतिहासिक रूप मे महत्वपूर्ण योगदान रहा हैं । नेपाल का पहला विद्रोह कहें या जन आन्दोलन वह १०४ बर्ष पुरानी राणा शासन विरोधी संघर्ष हि था । जिस ने नेपाल को नई दिशा दि । वि.स. २००७ साल का राणा शासन के खिलाफ मे हुआ मुल्क का इस पहला आन्दोलन का केन्द्र मधेस हि रहा था । इस मे मधेसी समुदाय का योगदान को कदापि भी अनदेखा नही किया जा सकता हैं । साथ हि, इस आन्दोलन मे भारत की भूमिका सिर्फ प्रेरक ही नही रहा हैं, अपितू भारतीय जनगण का सक्रिय योगदान भी रहा हैं ।

जब तक भारत ब्रिटीस शासन से मुक्त नही होगा, नेपाल मे राणाओं से मुक्ति नही मिलेगी । इस तथ्य को मनन कर नेपाल के वी.पी. कोइराला, डा. डिल्लीरमण रेग्मी, कृष्ण प्रसाद भट्राई, मातृका प्रसाद कोइराला, गणेश मान सिंह, सुवर्ण शमसेर राणा, महेन्द्र विक्रम शाह के समानान्तर मधेस के भद्रकाली मिश्र, महेन्द्र नारायण निधी, रामेस्वर प्रसाद सिंह, गजेन्द्र नारायण सिंह, काशीप्रसाद श्रविास्तव लगायत कयौं नेताओं ने अपने छात्र जीवन और संघर्ष के दौरान भारत मे रहकर नेपालीयों को संगठित करने का काम किया था । इन मे कई भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन मे जेल भी गये । वही जय प्रकाश नारायण, डा. राम मनोहर लोहिया, आचार्य कृपलानी, अशोक मेहत्ता, विजयलक्ष्मी पण्डित, श्रीपद अमृत डांगे, सी. नम्बूदरी पाद, मधु दण्डवते, सुरेन्द्र मोहन, मोहन धारिया, अरुणा आसफ अली, प्रेम भासीन, सरयु प्रसाद मिश्र, सुरज नारायण सिंह, अच्युत पटवर्धन, काशी प्रसाद सिंह, फणिश्वर नाथ रेणु, रामबृक्ष वेणीपुरी जैसे भारतीय राजनीतिक-साहित्यिक हस्तीओं ने नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलन मे खुल कर हिस्सा लिया । इस का अपना ही एक इतिहास और लम्बा फेहरिस्त हैं ।

वि.स. २००७ साल के क्रान्ति मे मधेसी का भूमिका

नेपाल मे राणा शासन के उत्कर्ष के दौरान वि.स. १९९७ मे चार क्रान्तिकारियों को मृत्यूदण्ड दिया गया था । इस मे एक शुक्रराज शास्त्री थें । शहीद शुक्रराज शास्त्री स्वयं आर्य समाज के शिष्य थे । उन्होने भारतीय आर्य समाज से प्रेरणा लेकर हि नेपाल मे राजनीतिक सुधार का मांग किया था । भारत मे आर्य समाज आन्दोलन के प्रणेता स्वामी दयानन्द सरस्वती से प्रभावित होकर नेपाल के मधेस क्षेत्र मे राजालाल आर्य, भगवान दास, रघुनाथ प्रसाद गुप्ता एवं उदयराज लाल जैसे सुधारकों ने बीरगंज, लुम्बिनी लगायत के क्षेत्रों में राणा शासन का सक्रिय विरोध किया था । भारतीय स्वाधिनता आन्दोलन के दौरान महात्मा गांधी से प्रभावित होकर जनकपुर में पं. रामाकान्त झा के अगुवाई मे बोध प्रसाद उपाध्याय, देवशंकर गिरी, श्रीकान्त ठाकुर, बौएलाल झा, अनिरूद्ध प्रसाद सिंह, कमलकान्त चौधरी, जमुना प्रसाद सिंह, बलभद्र चौधरी, रामदुलार साह, पं. रामचन्द्र झा, राजेश्वर निधी, महंथ गोकुल गिरी, गंगेश्वर झा तथा गुलाब नारायण झा समेत के लोगो ने राणा विरोधी मुहिम को आगे बढाया । बाद में जब नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ तब पं. रामाकान्त झा इसके संस्थापक सदस्य भी बने । नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में महोत्तरी के सरोज कोइराला, नरेन्द्र रेग्मी और सप्तरी के रूद्र प्रसाद गिरी, विराटनगर के दयाशंकर गुप्ता, नेपालगंज के योगेश्वर मिश्र आदि लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।

नेपाल का राणा विरोधी आन्दोलन मे सप्तरी जिले का हनुमाननगर प्रकरण को भुलाया नही जा सकता हैं । सन् १९४२ के भारत छोडो आन्दोलन मे गिरफ्तारी से बचकर नेपाली भूमि से आन्दोलन का संचालन करने के लिए प्रसिद्ध भारतीय नेतागण जय प्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन,

काशी प्रसाद सिंह तथा दो तीन और लोग सप्तरी जिला कोइलाडी गांव मे आए थे । ब्रिटीस अधिनस्थ हिन्दुस्तान की पुलीस तथा गुप्तचर उनके पीछे लगी थी । बाद मे ब्रिटीस सरकार के दबाव मे इन्हे गिरफ्तार कर हनुमाननगर के जेल मे रखा गया । तब सप्तरी के मधेसियों ने हनुमाननगर जेल पर शसस्त्र आक्रमण कर सभी क्रान्तिकारी भारतीय नेताओं को छुडाया था । इस पुरी अभियान मे नेपाल के जयमंगल प्रसाद सिंह, चतुरानन सिंह, तारिणी प्रसाद सिंह, रामेश्वर सिंह, दल बहादुर आदि का मुख्य मुख्य भुमिका रहा था । उस घटना में नेपाली गारद का एक संतरी मारा गया था । इसका असर यह हुआ कि नेपाल की पुलिस का नेपाली क्रान्तिकारियों पर और ज्यादा आतंक बढ गया । गिरफ्तारी और दमन शुरू हुआ । इस प्रकरण मे २२ लोगो को गिरफ्तार कर काठमाण्डू चलान किया गया और १२७ व्यक्ति को राजविराज जेल में रखा गया । काठमाण्डू जानेवाले मे सर्वश्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, चतुरानन सिंह, जयमंगल सिंह, मीन बहादुर सिंह, तारिणी प्रसाद सिंह, रामजी सिंह, शत्रुध्न प्रसाद सिंह, विन्देश्वरी प्रसाद सिंह, अखण्ड नारायण सिंह, रामदत्त कोइराला, जे.सी. समर बहादुर प्रजापत, कामानन्द मिश्र, नेबू मण्डल, अब्दुल मियां, कृष्णवीर कामी, किसन दुसाध, विष्णुध्वज श्रेष्ठ, बैजनाथ उपाध्याय, आनन्दी प्रसाद सिंह, चन्द्र नारायण सिंह, देवनारायण सिंह, सेवक माझी थे । इन्होने कठोर कारबास की सजा भुक्तान किया । अब्दुल मियां और कृष्णवीर कामी तो जेल मे ही शदीह हुए ।

नेपाल में राणा शासन विरोधी प्रजातान्त्रिक आन्दोलन में विराटनगर का आन्दोलन और सत्याग्रह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है । वि.स. २००५ साल मे विराटनगर जूट मिल और मोरङ कॉटन मिल से नेपाल के इतिहास में पहला मजदूर हड्ताल हुए । इस हडताल का नेतृत्व वी.पी. कोइराला, गिरिजा प्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, नैनालाल बोहरा, दिनेश दुबे, मुन्नीलाल चौधरी, इन्द्रप्रताप सेन, बंशीधर दास, रघुनाथ गुप्ता आदि ने किया था । इस आन्दोलन में पंचानन्द दास, पुरन सिंह का भी काफी योगदान रहा । विराटनगर मजदूर आन्दोलन में ६ मजदूर शहीद हुए ।

वि.स. २००३ साल मे कलकत्ता मे नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ । इस का स्थापना सभा मे नेपालगंज के सुविख्यात नेता जागेस्वर मिश्र ने भाग लिया था । इस के बाद वि.स. २००४ साल मे बिराटनगर का सीमावर्ती जोगबनी मे नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ । जिसमें मातृका प्रसाद कोइराला को कार्यवाहक सभापति बनाया गया । इस सम्मेलन में महेन्द्र नारायण निधी और पं. रमाकान्त झा लगायत कई मधेसी क्रान्तिकारी सम्मिलित थे । यहीं से देश व्यापी सत्याग्रह आन्दोलन की घोषणा की गयी । मधेस के आन्दोलनकारीयों ने विराटनगर, वीरगंज, लुम्बिनी आदि स्थानों पर सत्याग्रह आन्दोलन को तीव्र किया । लुम्बिनी क्षेत्र के सत्याग्रह में भोलानाथ शर्मा, दयाशंकर मुन्शी, काशीनाथ गौतम आदि को बन्दी बनाकर पहाड के जेल में डाल दिया गया । नेपालगंज क्षेत्र मे कुवँर कल्लु सिंह ने आन्दोलन को बढाया । सत्याग्रह आन्दोलन के क्रम में जनकपुर धाम में सरयुग चौधरी, सुन्दर झा शास्त्री, आशिष भगत, मिश्रीलाल गुप्ता, लक्ष्मण साह, मेध प्र. उपाध्याय, भीष्मजंग केसी, दिगम्बर झा, बच्चा झा, बल बहादुर मगर, निर्गुण यादव आदि लोग गिरफ्तार हुए । कुछ महीने बाद सरोज कोइराला, महेन्द्र नारायण निधी, नकुल बहादुर सिंह तथा पण्डित रमाकान्त झा और वीरगंज में नथुनी शाह, ठाकुर कुमार आदि गिरफ्तार हुए । वीरगंज में ही सचेन्द्र नारायण चौधरी और हंसराज ठाकुर सक्रिय थें । धनुषा-महोत्तरी क्षेत्र मे भद्रकाली मिश्र और रामनारायण मिश्र ने लोकसेवा संघ स्थापना की । इस अभियान के दौरान ज्ञानी शंकर गिरी, महावीर शर्मा, श्याम सुन्दर शर्मा, आनन्दी लाल झुनझुनवाला, राधा प्रसाद चौधरी आदि पकडे गए । वि.स. २००६ साल मे जलेश्वर जेल तोडकर निर्गुण यादव फरार हो कलकत्ता पहुंचे । सिरहा के कपिलेश्वर यादव २००४ साल मे ही नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस के सदस्य हुए थे । वे बैरगनिया सम्मेलन के भी एक सक्रिय सहभागी थे । वि.स. २००७ साल के जनक्रान्ति मे सिरहा जिला मे देवनाथ दास यादव, राजदेव गोइत, कुलानन्द झा, बलदेब दास यादव, मित्रलाल गिरी जैसे व्यक्तिओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया था । इस क्रम मे वर्दीया मे राधाकृष्ण थारु, दांग मे परशु नारायण चौधरी और कपिलवस्तु मे शिव प्रताप शाह आदि ने ऐतिहासिक भूमिका का निर्वाह किया ।

राणा शासन का अन्त्य के लिए महत्वपूर्ण फैसला भी मधेस मे ही लिया गया । वि.स. २००७ साल आश्विन १० गते रौतहट जिला का सीमा पार के बैरगनिया मे नेपाली कांग्रेस का अधिवेशन हुआ । इस

अधिवेशन में राणा शासन के खिलाफ में सशस्त्र क्रान्ति करने का निर्णय लिया गया । यही से राणा शासन विरोधी आन्दोलन मे उफान आया । सब से पहले बीरगंज मे फिर बिराटनगर मे और सर्वत्र मुक्ति सेना ने राणा फौज पर शसस्त्र आक्रमण किया । अनेक मोर्चा पर मधेसी लोग भी साथ साथ लडें । शसस्त्र आन्दोलन के दौरान पश्चिमी क्षेत्र मे काशी प्रसाद श्रीवास्तव, डा. के. आई. सिंह, खड्ग बहादुर गुरूङ, गोविन्द प्रसाद शर्मा, लक्ष्मी नारायण अधिकारी, बासदेव त्रिपाठी, प्रेमचन्द्र अग्रवाल, कृष्णदास भक्त, उदयराज लाल, रामवरन शर्मा, दशरथ प्रसाद एवं भाग्यनाथ दुबे का योगदान उल्लेखनीय है । मधेसी महिलाओं का भी एक विद्रोही सेना कौलपति मिश्र तथा युमना देवी के नेतृत्व में गठित हुई थी । क्रान्ति सम्बन्धी तथ्यों का प्रचार-प्रसार करने के लिए काशी प्रसाद श्रीवास्तव ने नई दिल्ली से "फ्रि नेपाल" नामक अंग्रेजी पत्र के प्रकाशन की व्यवस्था की । कुँवर कल्लू सिंह ने नेपालंज में आन्दोलन छेडा । बारा तथा रौतहट जिलों के विद्रोहियों ने भागवत यादव तथा शिव प्रसाद सिंह के नेतृत्व में कलैया एवं गौर बजार पर आधिपत्य जमाया । विद्रोहियों के नेता रति सन्यासी और नन्दू साह के साथ बीसों विद्रोही गौर बजार में राणा सैनिकों की गोलियों के शिकार बने । इसी क्रान्ति के दौरान जनकपुरधाम में राणा की फौज से लडते हुए मुक्ति सेना के प्रेम सिंह और कंचन मुखिया शहीद हुए । वीरगंज के मोर्चा पर बीसों शहीद हुए । पश्चिम के शसस्त्र कारवाही मे राणा फौज ने गोलिया बरसाई जिसमें मदन पाण्डेय, रामानुज पाण्डेय, कृपा दयाल सिंह तथा कृष्णदास भक्त जैसे लोग शहीद हो गये ।

वि.स. २००७ साल के सशस्त्र क्रान्ति मे कई भारतीयों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था । विहार फारबिसगंज निकट के निवासी फणीश्वर नाथ रेणु एक विख्यात रचानाकार थें । कोलकाता निवासी भोला चटर्जी एक सुप्रसिद्ध पत्रकार थें । ये दोनों २००७ साल के क्रान्ति मे शसस्त्र क्रान्तिकारी योद्धा के रूप मे लडे थे । इस युद्ध में जोगवनी के भावुक गुरूजी, फेकन चौधरी, विहार विरपुर के डी.पी. शर्मा, पटना के देवेन्द्र प्रसाद सिंह, लखनलाल कपूर, पूर्णिया जिला सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव नरसिंह नारायण सिंह, कमरेड भोला नाथ मण्डल, विहार फारबिसगंज के सरयु मिश्र को भुलाया नही जा सकता हैं । भारतीय नागरिक डाक्टर कुलदीप झा कुशहा के मोर्चा पर शहीद हुए ।

मधेसी किसानों का बलिदान

शसस्त्र आन्दोलन के दौरान ही वि.स. २००६, श्रावण के ६ गते को नेपाल-भारत के बीच शान्ति एवं मैत्री संधि हुई । वि.स. २००७ साल फागुण ७ गते निरंकुश राणा शासन का अन्त हुआ । किन्तु मधेसी जनता को कोई अधिकार नहीं दिया गया । देश की आधी आबादी होने के वावजूद पहला अन्तरिम सरकार मे वह भी भारत के दबाव पर भद्रकाली मिश्र को मंत्री बनाया गया । राणा शासन के समाप्ति के बाद नेपाल का मधेस मे नई जागरण का प्रभाव पडा । मधेस के किसानों ने अपनी बेहत्तर जीवन के लिए कई जिलो मे किसान आन्दोलन किया । इन आन्दोलनों को सैनिक बल पर कुचला गया । कई मधेसी किसान शहीद हुए । वि.स. २००७ साल मे ही रौतहट मे किसान आन्दोलन के नेता शिव प्रसाद सहित अनेक किसानें की हत्या की गयी । वि.स. २००९ साल में रौतहट के अशर्फी शाह, २०११ साल में सिरहा के बहादुर सदा, बारा के मुगालाल महतो और २०१४ साल में सप्तरी के अधोरी यादव शहीद हुए । वि.स. २००८ साल, बैशाख २० गते वर्दिया में किसानो ने जमीन्दारो के विरूद्ध संघर्ष किया । जिसमें सरकार की गोलियो ने कई किसानों को मौत के घाट उतार दिया ।

पहला जन निर्वाचित सरकार और मधेसी समुदाय

राणा शासन के समाप्ति के बर्षो के वाद वि.स. २०१५ साल फागुण माह मे प्रथम आम निर्वाचन हुआ । इस प्रथम आम निर्वाचन मे नेपाली कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने पर वी. पी. कोइराला के नेतृत्व में सरकार गठित हुई । नेपाल के इतिहास में पहली बार जन निर्वाचित सरकार मे कुछ मधेसियों को भी सहभागी बनाया गया । जिसमें रामनारायण मिश्र, परशुनारायण चौधरी, सूर्यनानाथ दास यादव और शिव प्रताप शाह मंत्रीमण्डल में पहुँचे । इस सरकार के कार्य काल मे नेपाली भाषा के साथ हिन्दी को द्वितीय राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दिया गया । संसद के दोनों सदनों में तराई के प्रतिनिधियों को हिन्दी

भाषा में अपने विचार रखने का मौका मिला । रेडियो नेपाल से हिन्दी मे प्रसारण करने की स्वतन्त्रता प्रदान की गई । श्री उमाकान्त दास के सम्पादकत्व तथा प्रकाशकत्व में हिन्दी दैनिक नेपाली समाचार पत्र का प्रकाशन आरम्भ हुआ । परन्तु मधेसी के प्रति नीतिगत रूप से विद्यमान रहे भेदभाव और असमानता समाप्त करने के दिशा में कोई ठोस कार्य नही किया गया ।

राजा महेन्द्र का सैनिक तानाशाही : मधेसीयों ने लडी लडाई

वि.स. २०१७ साल पुस १ गते के दिन राजा महेन्द्र ने सैनिक कू किया । इस के वाद निर्वाचित संसद को भंग कर दिया । नेपाल के सभी राजनीतिक दलों को अवैध घोषित करके उनकी सम्पूर्ण गतिविधिया समाप्त कर दी गई । प्रजातन्त्र के हत्या के प्रतिरोध में सम्पूर्ण मधेस मे विरोध प्रदर्शन हुआ । वि.पी. कोइराला गिरफ्तार किये गए । सूवर्ण शमसेर भारत मे थे । सूवर्ण शमसेर नेपाली कांग्रेस का कार्यवाहक अध्यक्ष बने । वि.स. २०१७ साल माघ १२-१४ गते तक पटना मे नेपाली कांग्रेस का सम्मेलन हुआ । कांग्रेस ने देशव्यापी शसस्त्र आन्दोलन चलाने का निर्णय लिया । इस सम्मेलन मे तत्कालिन नेपाल प्रजा परिषद (मिश्र) के अध्यक्ष भद्रकाली मिश्र, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी के महासचिव काशीप्रसाद श्रीवास्तव और नेपाल तराई कांग्रेस के महामंत्री रामजनम तिवारी ने भाग लिया था । नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व मे हुआ शसस्त्र संघर्ष मे वि.स. २०१९ में सुखदेव सिंह को राजविराज के सैनिक बैरक मे गोली का शिकार बनाया गया । राजा बिरोधी कार्यो का व्यवस्थापन करने के आरोप मे रक्सौल में कांग्रेसी नेता विश्वनाथ प्रसाद अग्रवाल पर प्रहार किया गया । वि.स. २०१८ साल, माघ ९ गते को छात्र नेता दुर्गानन्द झा ने जनकपुर भ्रमण के दौरान राजा महेन्द्र पर घातक बम फेंका । विस्फोट से राजा की कार क्षतिग्रस्त हुई किन्तु राजा बच गये । कुछ महिनों के वाद दुर्गानन्द झा को मृत्यूदण्ड दिया गया । इसी मुकदमे मे अरविन्द कुमार ठाकुर को आजीवन कारबास की सजा हुई । बीरगंज मे बम बिस्फोट किया गया । इस काण्ड मे दल सिंह मगर और दु:खा सहनी को १६ वर्ष तक जेल मे रहना परा । योगी साह को १० वर्ष कैद भुगना पडा । कपलेश्वर झा, कपलेश्वर लाल को आजीवन कैद की सजा दिया गया । पंचायती व्यवस्था के दौरान कई नेताओं को भारतीय सीमा क्षेत्र मे मार दिया गया । वि.स. २०१८ साल के संघर्ष मे बारा मे भागवत यादव और रुपन्देही मे सत्यनारायण मल्लिक ने अतुलनीय भूमिका निर्वाह किया ।

मधेसी समुदाय ने राजा महेन्द्र के द्वारा लागू किया गया सर्व सत्तावादी पंचायती व्यवस्था को स्वीकार नही किया । राजा के दृष्टिकोण मे भी मधेसीयों के प्रति घोर अविश्वास उत्पन्न हुआ । इस के परिणाम स्वरुप पंचायती व्यवस्था के दौरान कई मधेस विरोधी नीति और निर्णय लिया गया । मधेस के दक्षिणी क्षेत्रो मे पहाड और भारत के कई जगहों से पहाडी समुदाय के लोगों को लाकर बसाया गया । नेपाल मे मधेसी समुदाय को लक्षित कर वि.स. २०२० साल मे नागरिकता कानून लागू किया गया । इस कानून के लागू होने से दशौं लाख मधेसियों को नागरिकता देने से इन्कार कर दिया गया । परिमाण स्वरूप मधेस के कई भाग मे नेपाल नागरिकता कानून का प्रति को जलाया गया । मधेस मुक्ति मोर्चा के नेता सत्यदेव मणि त्रिपाठी एवं विश्वनाथ तिवारी के नेतृत्व मे रूपन्देही मे विरोध प्रदर्शन हुए । इस आन्दोलन के दौरान लक्ष्मी नारायण झा, श्यामलाल मिश्र, देवकी नन्दन गुप्ता, परमहंस यादव आदि को दण्डित किया गया । पंचायती व्यवस्था के दौरान सर्व प्रथम मधेस मे भूमिसुधार और इस के तहत अनिवार्य बचत कार्यक्रम लागू किया गया था । भूमि सुधार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ही मधेस मे रहे जमिन्दारों का जमीन हडप कर पहाडी समुदाय के लोगों को बसाना था । पंचायती सरकार की नीति के चलते मधेसियों में आक्रोश फैलता गया । अनेक जिलों में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ । वि.स. २०२३ साल मे नवलपरासी जिला के परासी में हजारौं किसानों ने सरकारी अधिकरियों के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया । इस दौरान पुलिस की गोली से ९ किसान मारे गये । आन्दोलन को कुचल दिया गया । किसानो का शेषण करने के लिए वि.स. २०२१ साल मे ही अनिवार्य बचत योजना शुरू की गई । वि.स. २०२६ साल मे कपिलवस्तु जिला के तौलिहवा में किसानों ने इस सरकारी नीति का विरोध मे कडा प्रदर्शन किया । पुलिस का हिंसक दमन चक्र चला, जिसमें २३ किसानों की मृत्यू हुई । इन सभी घटनाओं से मधेसी समुदाय मे एक

विश्वास बना कि, सर्व प्रथम अधिनायकवादी पंचायती व्यवस्था का खात्मा हो फिर मधेसीयों की अधिकार की लडाई लडी जाएगी ।

नेपाल का राजनीतिक इतिहास मे नेपाली कांग्रेस का उल्लेखनीय भूमिका रहा हैं । राणा शासन के खिलाफ का आन्दोलन क्रांग्रेस के ही नेतृत्व मे हुई थी । उस वक्त राणा शासन से मुक्ति चाहने बालों के लिए नेपाली कांग्रेस ही एक मात्र पार्टी थी । वि.स. २००७ साल से पहले मधेस के बडे जमीन्दार भी भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन से प्रभावित होकर नेपाल मे राणा शासन से मुक्ति चाहते थें । पढे लिखे नौजवान मे तो यह चाहना थी ही । मधेसी समुदाय के लोगों का नेपाली कांग्रेस से पुराना और गहरा ताल्लुकात का यही मुख्य कारण रहा हैं । सम्बन्ध और सरोकार का इन्ही तथ्यों के आलोक मे मधेसी लोग पुस्ता दर पुस्ता नेपाली कांग्रेस मे लगते गए । नेपाली कांग्रेस द्वारा संचालित २००७ साल का, २०१८ साल का, २०२९-३० साल का शसस्त्र आन्दोलनों मे और २००७ साल से लेकर २०६२-६३ साल तक का सभी शांतिपूर्ण जन आन्दोलनों मे मधेसी समुदाय से आये हुए युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा हैं । नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व मे हुए सशस्त्र संघर्ष के क्रम में वि.स. २०१८ साल मे ही रौतहट के बंकुल मे रामविलास राय यादव, पर्सा मे सुलेमान मियां, बारा के भोला शाह कानू और सप्तरी सूवर्णपट्टी के कैलु चौधरी थारू शहीद हुए । इसी साल रौतहट के शेष पांचू और गणेश राउत कुर्मी की हत्या करवायी गयी । वि.स. २०२० साल मे सेन्ट्रल जेल मे बन्दी रहे भरत गोपाल झा को मार दिया गया, २०१९ साल मे बारा के हरि सहनी मल्लाह, परीक्षण ठाकुर लोहार, मोहन शाह कानू, रामचन्द्र महतो कोइरी और रौतहट के सुखारी हजरा पासवान शहीद हुए । इसी दौरान वि.स. २०१९ साल आश्विन २४ गते धनुषा के सम्सी मे शिवचन्द्र मिश्र शहीद हुए । रौतहट के जलील मियां को वि.स. २०१९ साल मे गिरफ्तार कर २०२० साल मे उन्हे बीरगंज जेल मे मारा गया ।

वि.स. २०१८ के वाद पंचायती व्यवस्था के विरुद्ध का आन्दोलन मे बडी तेजी आई । पूरी देश के साथ मधेस मे हजारौं लोग गिरफ्तार किये गए । सयौं के संख्या मे लोग भारत प्रवास मे गए । नेपाली कांग्रेस के साथ तथा अन्य प्रतिबन्धित संगठनों से संलग्नता के आरोप मे मधेसी समुदाय के कई व्यक्ति बर्षो तक जेल मे रहें । झापा के तुरसा हेमरम सतार, गुलुम राजवंशी, डिगेन्द्र राजवंशी, मंगल मर्दी सतार, चेर्खा टुडु सतार, छेना सतार, छोटका सतार, गोपाल सतार, घुमा सतार, देनावास्के सतार, नारायण सतार, मोरंग के गौराचन्द्र वेरा बंगाली, हदराज बोहरा, शिवेस्वर मण्डल, उमेश गिरी, डा. चन्द्रनारायण मल्लिक, युगल किशोर राय, किशोर सिंह खवास, ज्ञानलाल सिंह खवास, यदुनन्दन गच्छदार, बिजय सिंह खवास, चेत नारायण खवास, हरिनारायण चौधरी, जोगीलाल यादव, सुनसरी के सुकदेव मेहता, नकछेदी महत्तो, बिजय गच्छदार, सुलेमान मियां, लक्ष्मण मेहत्ता, खुशीलाल चौधरी, गुलेस्वर खवास, लक्ष्मण साह हलुवाई जैसे लोग लगातार बर्षौं तक जेल मे रहे । सप्तरी जिला के इन्द्रदेव सिंह, रामराजा प्रसाद सिंह, गंगाधर झा, चन्द्र शेखर झा आजाद, मधुकान्त सिंह, खुशीलाल मण्डल, अनिस अंसारी, भोला ठाकुर, डा. दिवाकर दत्त, गणपति मण्डल, राजेस्वर प्रसाद साह, जय प्रकाश आनन्द, मधुरी मुसहर, जगन्नाथ दास, विश्वनाथ गुप्ता, जय सुन्दर यादव, खुशीलाल सदा मुसहर, झमेली सदा मुसहर, धनेस्वर सदा मुसहर आदि बर्षो जेल मे रहें । श्रीकांत मंडल, कमल सहनी, गंगाराम साह, विश्वेस्वर साह, लाल बहादुर राय, बीरेन्द्र सिंह ननकू, रघुनन्दन गुप्ता, कुसुमलाल कामी लगायत के व्यक्ति कयौं बर्ष जेल तथा भारत प्रवास मे रहे । राजा के आदेश से सयकडों लोगो का सम्पति जफ्त किया गया । मधेसी समुदाय से धनुषा के ज्ञानीशंकर गिरी, निर्गुण यादव, रामचन्द्र अधिकारी, मौना धामी, राजदेव यादव, महन्थ यादव, बहरु यादव, कपिलेस्वर झा, महोत्तरी के रामचन्द्र सिंह, जोगेन्द्र सिंह, महावीर सिंह, भद्रकाली मिश्र, चिन्ताहरण सिंह, सियावरण, सप्तरी के जुगेश्वर गुप्ता, रामेस्वर प्रसाद सिंह, केदार प्रसाद सिंह, देवनाथ दास यादव, रामएकबाल, सुनसरी के रामेस्वर यादव, मोरंग के सुलेमान मियां, झापा के तुरसा हेमरम सतार, रौतहट के रामस्वरुप यादव, बृषनन्द वर्मा, शेख अब्दूल मजीद, शेख इद्रिस, शेख फरमान, सर्लाही के रामचन्द्र राय, पर्सा के केदार गिरी, रामजनम तिवारी, बारा के भागवत प्रसाद यादव, रुपन्देही के काशीप्रसाद श्रीवास्तव जैसे लोगों का सम्पूर्ण सम्पति को सरकार ने जफ्त किया । सिरहा के सूर्यनाथ दास यादव, नथुनी सिंह दनुवार, प्रमोद ठाकुर,

बलदेव दास यादव जेल मे रहें । धनुषा के महेन्द्र नारायण निधी, ज्ञानीशंकर गिरी, विमलेन्द्र निधी, दिगम्बर राय, स्मृति नारायण चौधरी, महादेव साह, रामचन्द्र मण्डल, राम इकवाल मण्डल, जगदीशचन्द्र गुप्ता, बृषेशचन्द्र लाल, महेशशंकर गिरी, रविन्द्र ठाकुर, राम नारायण मण्डल, चन्द्रेस्वर मण्डल केवट, चन्द्रदेव ठाकुर, देवली मण्डल धानुक, राजेश्वर ठाकुर बडही, महोत्तरी के महन्थ ठाकुर, महेस्वर प्रसाद सिंह, महेन्द्र कुमार मिश्र, सुरेश आजाद, रामचन्द्र तिवारी, सर्लाही के राम जीवन सिंह भूमिहार, भीखारी मंसुर, रामचन्द्र राय यादव, बिजय प्रताप सिंह, रौतहट के शेख इद्रिश, शेख फजले हक, चन्द्रशेखर प्रसाद ठाकुर, भरत प्रसाद यादव, बिन्दा सहनी, परदेशी राउत कुर्मी, भगल साह कलवार, मगनी साह तेली, सूर्यराय यादव, बारा के युगल किशोर चौधरी, भोला मियां ठकुराई, भिखारी पण्डित, राम बिलास गुप्ता कलवार, रामजनम बडही, श्याम किशोर कुसवाहा, पर्सा के दुःखा सहनी, आत्माराम ओझा, डा. जमुना प्रसाद, रामजनम तिवारी, सुरेन्द्र चौधरी, मगनी साह, गोपाल राउत कुर्मी, विश्नाथ महतो कोइरी, लोचन हजरा दुसाध, चितवन के बलराम बंगाली, नवलपरासी के नरबहादुर चौधरी, रुपन्देही के लाल चौधरी, टेनइ चमार, पल्टन थारु, काकुर नाउँ, बिक्रम थारु, दांग के अशोक कुमार चौधरी, बांके के हिरा सिंह पंजाबी जैसे मधेसी समुदाय के लोग कयौं बर्ष तक कठोर कारबास का सजाय भोगा । यह तो एक अपूर्ण तथ्यांक है, जिस का उल्लेख स्मरण के आधार पर यहां किया गया हैं । पंचायती व्यवस्था के दौरान जेल जाने बाल मधेसीयों का संख्या इस से कई गुणा ज्यादा हैं । इस पर खोज करना होगा ।

मधेसी युवाओं का अतुलनीय बलिदान

पंचायती व्यवस्था के खिलाफ मे हुआ सभी छात्र आन्दोलनों मे मधेसी समुदाय के छात्रों को योगदान अतुलनीय रहा हैं । वि.स. २०२८ साल मे पंचायती सरकार के द्वारा लागू की गई नयां शिक्षा नीति के विरोध मे देशव्यापी आन्दोलन हुआ । इस आन्दोलन का सर्वाधिक प्रभाव मधेस के जिलो मे रहा । धनुषा जिला का यदुकहा मे छात्र प्रदर्शन पर पुलिस ने निर्ममता पूर्वक गोली चलाई । वि.स. २०२९ साल, आश्विन १ गते पुलिस का गोली से १७ बर्षीय छात्र कामेश्वर मंडल का देहान्त हुआ । गोली प्रहार से ही सातवें कक्षा का दुसरा छात्र कन्नी गोइत और १५ बर्षीय कुशेश्वर मंडल भी उसी रोज शहीद हुए । इस गोली काण्ड मे घायल ग्रामीण सवकत कवारी और नक्काराज नामक व्यक्ति का दूसरे रोज मृत्यू हुई । एक और लोग मारे गये । वि.स. २०३६ साल का विद्यार्थी आन्दोलन मे जेष्ठ ६ गते महोत्तरी के करैया में छात्र नेता मिथिलेश दुबे और उसी रोज सर्लाही के हरिपूर्वा मे ललन राय, अमृत शाह, शेख मियां, बुधन अंसारी, सूरत ठाकुर, इसरायल शेख, रामबाबू चौधरी तथा लालबन्दी मे इगल बहादुर, जर्घामगर ने शहादत्त प्राप्त की । इसी प्रकार ०३६ साल का छात्र आन्दोलन के दौरान ही ०३६ बैशाख १० गते के रोज सिरहा के माडैर मे जगदीश खत्वे, तसलिम मिया और रामेस्वर मंडल एक साथ ही पुलिस के गोली प्रहार से शहीद हुए । सिरहा के कर्जनहा मे २०३६ साल के जेठ ३ गते विद्यार्थीओं का प्रदर्शन पर पुलिस ने गोली चलाया । जिसमे छात्र नेता राम परीक्षण गडेरी शहीद हुए । दाङ मे रतन बहादुर चौधरी शहीद हुए । इसी साल के आन्दोलन मे धनुषा मे मुगालाल महतो, मोहन राम महतो मारे गए ।

वि.स. २०४२ साल मे नेपाली कांग्रेस ने सत्याग्रह संचालन किया था । इसी दौरान रामराजा प्रसाद सिंह का जनवादी मोर्चा के द्वारा गणतन्त्र स्थापना के मांग के साथ राजधानी काठमाण्डू मे कई जगह बम बिस्फोट करवाया गया । इस बम काण्ड के अनुसन्धान के नाम पर गिरफ्तार हुए डा. लक्ष्मी नारायण झा, सत्यनारायण साह, ईश्वर लामा, पद्म लामा, साकेत चन्द्र मिश्र, हरि भुजेल और दिलीप चौधरी को वेपत्ता कर उनकी हत्या कर दी गयी । रामराजा प्रसाद सिंह के निर्देशन और नेतृत्व मे हुआ इस बम काण्ड के अभियोग मे जनवादी मोर्चा के कई बिद्रोहीयों पर पंचायती सरकार ने गंभीर मुकदमा चलाया । इस मे रामराजा प्रसाद सिंह को मृत्यू दण्ड और उन का सम्पति का कुर्की, लक्ष्मण प्रसाद सिंह, प्रेम बहादुर विश्वकर्मा, बिश्वेस्वर मण्डल, पवन कुमार साह को मृत्यू दण्ड का फैसला सुनाया गया । खेमराज मायालु, बिश्वनाथ चौधरी, शिव कुमार विश्वकर्मा, राजेन्द्र झा, मजिद मियां, किशोरी साह, हरिदेव चौधरी, ईश्वरी ठाकुर, इन्द्र बहादुर विश्वकर्मा और दाताराम बजगाई को २० बर्ष तक का जेल सजाय दिया गया था । इस महान क्रान्तिकारी कदम मे भी अधिकांश मधेसी लोगों का ही सहभागिता रहा था ।

वि.स. २०४५ से पंचायती व्यवस्था के खिलाफ शसक्त जन आन्दोलन शुरु हुई । इसी साल पुस के २६ गते जनकपुर धाम में सत्यनारायण पाठक शहीद हुए । शिक्षक महादेव झा की मृत्यु हुई । वि.स. २०४६ साल फाल्गुन ९ गते धनुषा के यदुकहा मे हुआ भीषण गोलीकाण्ड में जानकी देवी यादव, भुवनेश्वरी देवी यादव, सोनावती देवी यादव, उदय शंकर मण्डल और रामनारायण यादव शहीद हए । देश की इतिहास मे महिला शहीद होने का यह पहला घटना था । इस के वाद चैत्र २४ गते राम विलास ठाकुर शहीद हुए । अन्य कई वारदातो मे सप्तरी के बिहारी चौधरी और सुरेश कुमार गुप्ता, रौतहट के मुकुट ओझा, बारा के वैद्यनाथ गुप्ता और दीपक गुप्ता (जिनकी रक्सौल में हत्या की गयी) शहीद हुए ।

नेपाल के कम्युनिष्ट आन्दोलन मे मधेसी योगदान

पंचायती व्यवस्था के विरुद्ध का संघर्ष मे नेपाल के कम्युनिष्ट आन्दोलन का भी अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान रहा हैं । कुछेक अपवाद वाहेक अनेक समूहों मे विभक्त कम्युनिष्ट नेता और कार्यकर्ताओं ने लम्बा संघर्ष किया हैं । नेपाल के कम्युनिष्ट आन्दोलन को व्यवस्थित करने के लिए भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी के तरफ से अयोध्या प्रसाद सिंह को नेपाल भेजा गया था । भारतीय नागरिक होने बावजूद वे वि.स. २००८ साल तक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी के पोलिटब्यूरो के सदस्य थे । इस दौरान के मधेसी नेताओं मे सप्तरी के सैयद कमर शाह जो वि.स. २०१० के पहला महाधिवेशन से नेकपा के केन्द्रीय सदस्य चुने गए थे । रौतहट के शेख फरमान जो वि.स. २०१५ साल के आम निर्वाचन मे कम्युनिष्ट पार्टी के तरफ से विजयी होने वाले कूल ४ व्यक्तियों मे एक थे । इन चार लोगों मे दो मधेस से विजयी हुए थे । सिरहा के भोगेन्द्र ठाकुर एक क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट नेता थे । वे वि.स. २०२८ साले ही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी के केन्द्रीय सदस्य चुने गए थे । उदयपुर जिला के लक्ष्मी नारायण चौधरी, सुनसरी के प्रभु नारायण चौधरी, सप्तरी के हिरालाल चौधरी, भदेस्वर प्रसाद साह, सत्यनारायण मंडल और जयकृष्ण गोइत, धनुषा के जोगिन्द्र साह काका, गणेश साह, महोत्तरी के जीवेन्द्र नाथ झा, महाविर प्रसाद सिंह और सीतानन्दन राय, सर्लाही (छतौना) के सुरेन्द्र सिंह, बारा के सोहन लाल चौधरी और गोपाल ठाकुर ऐसे अनेकन मधेसी व्यक्तिओं ने नेपाल मे कम्युनिष्ट आन्दोलन को सिंचा हैं । अनेकन् लोगों ने कम्युनिष्ट आन्दोलन के नाम पर शहादत पाया हैं । असंख्य लोग जेल के कठोर जीवन को भोगा हैं ।

सिरहा के बडहरा माल मे जन्मे बहादूर सदा मुसहर समुदाय के होते भी उन की राजनीतिक चेतना के कारण वि.स. २०११ साल सेना के द्वारा मारे गए । रौतहट जिला कम्युनिष्ट क्रियाकलाप का एक मुख्य केन्द्र रहा था । रौतहट के हरिहर यादव लगायत दुखीलाल चौधरी, छवील चौधरी, हरदयाल महतो, अमीन दर्जी आदि नेताओं का नाम उल्लेख्य हैं । कम्युनिष्ट आन्दोलन के क्रम मे ही वि.स. २०३२ साल मे रामाधीन महतो, मज्जुलद अहमद, हरिकृष्ण चौधरी, विरजू चौधरी और भेटला राजवंशी मारे गए । पंचायती व्यवस्था का शरुआती दौर के ही रूपन्देही जिला के मर्चवार में तत्कालिन मधेस मोर्चा के नेता रघुनाथ राय तथा कपिलवस्तु में रामजी मिश्र गोली के शिकार बनाये गये । सप्तरी के कम्युनिष्ट नेता जयकृष्ण गोइत और सत्यनारायण मण्डल लम्बे समय तक जेल मे रहे हैं । भारत के पश्चिम बंगाल से शुरु हुआ नक्सलवादी आन्दोलन का प्रभाव भी पूर्वी नेपाल के झापा, मोरङ जैसे जिलों में पडा । नक्सलवादी सोच का झापा संघर्ष के दौरान वि.स. २०२९ साल में झापा के ही वीरेन राजवंशी, वि.स. २०३३ साल में सिरहा के रामप्रीत यादव और मोरङ के वलेश्वर राय, वि.स. २०३६ साल में धनुषा के झप्सी मण्डल और २०४६ साल में झापा के छविलाल राजवंशी प्रहरी के द्वारा मारे गए । वि.स. २०४२ साल आश्विन ४ गते क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट नेता सूर्यनाथ यादव को सरकार ने कायरता पूर्वक हत्या की । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट नेता जय गोविन्द शाह ने जेल और बाहर रहकर आजीवन संघर्ष किया । वे करीब छ साल तक जेल में रहे थे । सिरहा जिला से एमाले पार्टी का संसद सदस्य रहे हेमनारायण यादव का वि.स. २०६० साल माघ १९ गते सेना के ब्यारेक मे हत्या कर दिया गया ।

मूल धार की मधेसी राजनीति

तराई कांग्रेस की स्थापना नेपाल की राजनीति मे एक दूरगामी महत्व का घटना था । सन् १९४७ मे भारत की स्वाधिनता और सन् १९५० (वि.स. २००७) मे नेपाल मे राणा विरोधी जन क्रान्ति के सफलता के दूसरे बर्ष ही २००८ साल मे तराई कांग्रेस स्थापना हुई थी । सब से महत्वपूर्ण बात तो यह है कि, जिस वक्त नेपाल के लोग अच्छी तरह से प्रजातन्त्र का अर्थ भी नही समझ पाए थे उस वक्त तराई कांग्रेस के संस्थापकों ने नेपाल मे मधेसीयों के साथ हो रहे विभेद का अन्त्य, प्रादेशिक संचना की मांग, भाषाई अधिकार के सवालों को जोडदार तरिके से उठाया था । सिरहा जिला निवासी बलदेव दास यादव और कुलानन्द झा के सक्रियता मे इस पार्टी का जन्म हुआ था । सिरहा के सीमावर्ती जयनगर क्षेत्र मे रुद्र प्रसाद गिरी, देवनाथ दास यादव, बलदेव दास यादव, कुलानन्द झा आदि नेपाल के राणा विरोधी और नेपाली कांग्रेस से सम्बन्धित व्यक्ति के रूप मे कार्यरत् थे । वे सभी बहुत बडे क्रान्तिकारी थे और साथ साथ भारतीय स्वततन्त्रता आन्दोलन मे भी सरिक हुए थे । परन्तु कुलानन्द झा और बलदेव दास यादव का चेतना भिन्न प्रकार का था । कुलानन्द झा राजनीति के प्रारम्भ से ही मधेसीयों के प्रति हो रहे विभेद से वाकिफ थे । उन का परिचय वी.पी. कोइराला से था । उन्होने २००७ के क्रान्ति के पश्चात ही मधेसीयों के प्रति हो रहे विभेद को हटाने के लिए क्रान्ति नायक वि.पी. कोइराला से संवाद किया । वि.पी. ने इसे साम्प्रदायिक सोच कह कर दुत्कार दिया । इस से कुलानन्द झा दुःखित हुए । उन का इसी विद्रोही तेवर के कारण २००७ साल मे जब वी.पी. कोइराला राणा-कांग्रेस अन्तरिम सरकार के गृहमंत्री थे, कुलानन्द झा को गिरफ्तार किया गया था । वि.स. २००८ साल मे सिरहा का कल्याणपुर जब्दी स्थित महादेव मन्दिर का धर्मशाला मे मधेसीयों की एक सभा बुलाई गई थी । इस सभा का अध्यक्षता बलदेव दास यादव ने किया था । यही कुलानन्द झा के अध्यक्षता मे तराई कांग्रेस का गठन हुआ । जनकपुर मे इस का घोषणा किया गया । तराई कांग्रेस के गठन के कुछ वाद ही कुलानन्द झा ने अपना सहोदर भाई वेदानन्द झा को पार्टी का अध्यक्ष बनाया । वेदानन्द पटना मे पत्रकारिता करते थें ।

वि.स. २०१५ साल का पहला आम निर्वाचन मे इस पार्टी ने संसद का कूल १०९ स्थान मध्ये तराई के २१ स्थान पर उम्मेदवार खडा किया था, परन्तु पार्टी को एक भी स्थान प्राप्त नही हो सका । राजा महेन्द्र के द्वारा संसदीय व्यवस्था को भंग किए जाने के वाद तराई कांग्रेस के तत्कालिन अध्यक्ष वेदानन्द झा भी गिरफ्तार हुए थें । वे संघर्ष मे टिक न सके और अपनी व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति के लिए राजा के कदम को समर्थन किया । वाद मे वे पंचायती व्यवस्था के तहत एक शक्तिशाली मंत्री बने । तराई कांग्रेस के कई प्रभावशाली नेतागण वेदानन्द झा के इस आत्म समर्पण से सहमत नही थे । उस समय के माहौल मे रामजनम तिवारी आदि नेताओं ने मूल्यांकन किया कि, पहले देश मे लोकतन्त्र कि स्थापना हो, फिर हम तराई की अधिकार के लिए लडेंगे । इस सोच के साथ तराई कांग्रेस के तत्कालिन महासचिव रामजनम तिवारी ने रक्सौल में सम्मेलन करके पहला कदम-प्रजातंत्र पुनर्स्थापना के नाम पर सुवर्ण शमसेर के मार्फत तराई कांग्रेस को नेपाली कांग्रेस में विलय कर दिया ।

मधेस-तराई की मुक्ति का सवाल

तराई कांग्रेस का नेपाली कांग्रेस मे विलय के वाद तराई के नाम पर संगठित रूप से कोई राजनीतिक गतिविधि नही रहा । पश्चिम तराई के वामपंथी विचारधारा से प्रभावित कुछ व्यक्तिओं ने तराई मुक्ति मोर्चा का गठन कर फाटफूट रूप मे कुछ कारवाही करने का उल्लेख मिलता हैं । इस से सम्बन्धित रहे व्यक्ति तराई कांग्रेस से भी जुडे थे । इस संगठन ने पश्चिम तराई के क्षेत्रों मे छापामार युद्ध संचालित करने का निर्णय किया था । वि.स. २०२० साल असार का पहला सप्ताह मे नेपाल सरकार के सैनिकों के द्वारा मोर्चा के नेता रामजी मिश्र का हत्या कर दिया गया । इसी तरह तराई मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ राय की भी शाही नेपाली सेना के द्वारा हत्या कर दी गयी । इन का हत्या रूपन्देही जिला के सीमावर्ती भारतीय शहर नौतनवा से अपहरण करके नेपाली सीमा के भीतर ला हत्या कर दी गयी । इसी तरह से सत्यदेव मणि त्रिपाठी की भी हत्या हुई ।

राजा महेन्द्र के द्वारा सैनिक बल पर शासन किए जाने बावजूद भी सुनसरी के रघुनाथ ठाकुर ने मधेस मुक्ति आन्दोलन को आगे बढाया । रघुनाथ ठाकुर नेपाल मे मधेसियों के प्रति हो रहे भेदभाव और राजनीतिक शोषण के विरूद्ध शांतिपूर्ण आन्दोलन के पक्षधर थे । वि.सं. २०१५ साल मे ही रघुनाथ ठाकुर ने "परतंत्र मधेस और उसकी संस्कृति" और वि.स. २०१६ साल में "मधेस आन्दोलन के प्रस्ताव ओर उनकी व्याख्या" नामक पुस्तक प्रकाशित की । वे एक सिद्धहस्त लेखक थे । उन्होंने विराटनगर से हिन्दी मे "राजहंस साप्ताहिक" और "मधेसी आवाज" नामक पत्रिका निकालनी शुरू की । वास्तव मे रघुनाथ ठाकुर ने ही सर्व प्रथम स्पष्ट व्याख्या के साथ मधेस की मुक्ति का सवाल को उठाया । उन्होंने मधेस एवं मधेसी के विकास के लिए मधेसी राष्ट्रीय पुलिस, फौज, कार्यपालिका, विधायिका, स्वतंत्र न्यायपालिका तथा लोक सेवा आयोग आदि का परिकल्पना कर इस की स्थापना के लिए आन्दोलन पर जोड दिया । उन्होंने मधेसी क्रान्ति को आगे बढाने के लिए "मधेस जन क्रान्तिकारी दल" नामक संगठन को जन्म दिया था । परन्तु, दुर्भाग्यवश वि.स. २०३८ साल जेठ माह मे सन्देहास्पद अवस्था मे वे मृत पाए गए । उन की मृत्यू भी सप्तरी और सिरहा जिला के सीमावर्ती एक भारतीय कस्बा मे हुई । उन के परिजनों के अनुसार नेपाल सरकार के षडयन्त्र के तहत उन का भोजन मे बिष मिलाकर हत्या कर दिया गया । रघुनाथ ठाकुर का देहावसान मधेस आन्दोलन का सब से बडा क्षति था ।

सदभावना पार्टी का उद्भव और पतन

नेपाल सदभावना परिषद और वाद मे नेपाल सदभावना पार्टी का जन्म नेपाली कांग्रेस का मधेसी समस्याओं पर रहा असहिष्णु व्यवहार के कारण हुआ । नेपाली कांग्रेस के भीतर शुरू से ही कुछ मधेसी नेतागण मधेस की समस्या को उठाते रहें । महोत्तरी के रामाकान्त झा ने वी.पी. कोइराला के सम्मुख मधेस के सवालो को एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में रखा था । वे नेपाली कांग्रेस के नेता थें । खास कर भद्रकाली मिश्र, गजेन्द्र नारायण सिंह, रामजनम तिवारी, रासबिहारी राय यादव, चैतु चौधरी, बलराम नायक, गंगाधर झा, रामचन्द्र मिश्र आदि नेतागण पंचायती व्यवस्था के दौरान लागू किया गया भूमि सुधार कार्यक्रम और नागरिकता सम्बन्धि कानून के वारे मे नेपाली कांग्रेस पार्टी के द्वारा मधेस मैत्री नीति अख्तियार करने पर दवाव देते रहे थे । नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष वी.पी. कोइराला जेल मे थें । सुवर्ण शमसेर पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष थें । कहा जाता हैं कि, सुवर्ण शमसेर मधेस की समस्यों के वारे मे कुछ हद तक सहानुभूति रखते थें । परन्तु, इस से साम्प्रदायिक भावना बढने का खतरा भी देखते थें । जेल से वि.पी. कोइराला के रिहाई के वाद उन्होने मधेसियो की समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया । कांग्रेस के पास नीतिगत रूप से मधेसियों के सम्बन्ध में कोई कार्यक्रम या कार्य योजना नहीं थी । पंचायती व्यवस्था के इस दौर मे ही राजसत्ता के द्वारा कडी शर्तो पर नागरिकता देने के लिए टोली गठन कर मधेस मे भेजने का निर्णय लिया गया । यह मधेसी समुदाय को नागरिकता से बेदखल करने का एक खुला षडयन्त्र था । इस के विरुद्ध नेपाली कांग्रेस मे रह कर ही गजेन्द्र नारायण सिंह, रामजनम तिवारी, रासबिहारी राय यादव, चैतु चौधरी आदि नेताओं ने एक पर्चा निकाला था । इन की बातों को अनदेखा किया गया । इन लोगों ने तराई की समस्या के सम्बन्ध में भारत के तत्कालिन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से मुलाकात कर दखल देने हेतू उन्हे अनुरोध किया । उन्होने नही सुना । इस के बाद बिशेषतः नेपाली कांग्रेस के पूर्वाञ्चल से जुडे हुए ये नेतागण भारत मे विपक्षी दल की नेता श्रीमति इन्दिरा गांधी से भेंट की, इन्दिरा गांधी मधेसियों के प्रति सहानुभूति रखती थी ।

लगभग इसी वक्त नेपाल मे डा. हर्क बहादुर गुरुंग का आप्रवासन सम्बन्धि प्रतिवेदन आया था । यह प्रतिवेदन मधेसीयो के खिलाफ मे था । वि.स. २०३९ साल मे डा. हर्क बहादुर गुरूङ के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में तराई मे बृहद् जन आक्रोश देखा गया । इसी माहौल मे नेपाली कांग्रेस के भितर रहे मधेसी नेताओं ने नेपाली सद्भावना परिषद् गठन करके इस रिपोर्ट का विरोध करने का फैसला लिया । पूर्वाचल से कांग्रेस के सदस्यों की सक्रियाता में नेपाल सद्भावना परिषद् जनकपुर धाम के नाम से गुरूङ प्रतिवेदन के विरूद्ध पर्चा निकाला गया । इसी पर्चा काण्ड में रामजनम तिवारी वीरगंज मे गिरफ्तार हुए । गजेन्द्र नारायण सिंह को महोत्तरी का पिपरा से गिरफ्तार किया गया । गजेन्द्र नारायण सिंह के अलावा दिलीप

सिंह, देव नारायण झा, रामकृष्ण साह आदि गिरफ्तार हुए थे । गजेन्द्र नारायण सिंह के ऊपर राजकाज अपराध सम्बन्धी मुद्दा चलाया गया । इन घटनाक्र मे प्रतिबन्धित रहे नेपाली कांग्रेस मौन रहा । बाद में कांग्रेस के कुछ मधेसियों ने नेपाली कांग्रेस पार्टी से विद्रोह करते हुए गजेन्द्र नारायण सिंह के संयोजकत्व में नेपाली सद्भावना परिषद् का गठन किया गया । जिसमें बलराम नायक उप संयोजक थे और अन्य सदस्यों में काशी प्रसाद श्रीवास्तव, गंगाधर झा, रामजनम तिवारी, श्यामलाल मिश्र, केदार यादव, राजेश्वर नेपाली, विश्वनाथ साह और दिलीप कुमार सिंह आदि थे ।

एक राजनीतिक मञ्च के रूप मे सद्भावना परिषद् का गठन कर आवाज उठाने के जूर्म मे तत्कालिन सरकार घोर असहिष्णु होकर मधेस के नेताओं पर साम्प्रदायिकता एवं क्षेत्रीयता की भावना फैलाने का आरोप लगाया । इसी इल्जाम पर राजकाज अपराध के कानून अन्तरगत रामजनम तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद साह, दिलीप कुमार सिंह, रामकृष्ण साह सहित कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेलें बन्द कर दिया गया । बीरगंज से गजेन्द्र नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया, वे काठमाण्डू में नागरिकता समस्या पर राष्ट्रीय स्तर को गोष्ठी करना चाहते थे । इस संघर्ष मे गजेन्द्र नारायण सिंह का व्यक्तित्व एक लडाकु नेता के रूप मे उभरा । उन्होने पंचायती व्यवस्था के संरचना मे ही चुनाव लडने का सोच बनाया । अपने सहयोगी अनिस अन्सारी को राजविराज नगर पंचायतका प्रधानपंच मे चुनाव लडाया । वे विजयी हुए । गजेन्द्र नारायण सिंह स्वयं सप्तरी से राष्ट्रीय पंचायत का चुनाव लडे । पहली बार पराजय के बाद दुसरी बार वे राष्ट्रीय पंचायत के सदस्य बन गये । उन का इस निर्णय को काफि विवादास्पद माना गया । राष्ट्रीय पंचायत में उन्होंने मधेसियों की नागरिकता समस्या, हिन्दी भाषा की मान्याता, मधेसी की पोशाक धोती, कुर्ता को राष्ट्रीय पोशाक के रूप में मान्यता, जनसंख्या के आधार पर राजकीय सेवाओं में सीट का आरक्षण, तराई की भाषा में सरकारी टेलिभिजन और रेडियो नेपाल से समाचार आदि प्रसारण की व्यवस्था और मधेसियों के पर्व त्यौहारों में सार्वजनिक छुट्टी की व्यवस्था जैसे सवाल को उठाया ।

वि.स. २०४७ साल बैशाख २-३ गते काठमाण्डू मे हुई एक छलफल के पश्चात सद्भावना परिषद को रूपान्तरित कर नेपाल सद्भावना पार्टी बनाना तय हुआ । यह बैठक गजेन्द्र नारायण सिंह ने बुलाया था । वि.स. २०४६ का फागुण ७ गते से नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व मे पंचायती व्यवस्था के खिलाफ पहला जन आन्दोलन का आह्वान किया गया था । इस जन आन्दोलन की सफलता के वाद पंचायती व्यवस्था का अन्त्य हुआ और वि.स. २०१७ साल से राजनीतिक दलों पर रहा प्रतिबन्ध हटाया गया था । इस के बाद ही खुली राजनीतिक वातावरण मे मधेसी समुदाय का अपना एक राजनीतिक पार्टी हो, इस अभिप्राय से नेपाल सद्भावना पार्टी का जन्म दिया गया । वि.स. २०४७ साल आषाढ का १५ गते जनकपुर धाम में नेपाल सद्भावना पार्टी का स्थापना महाधिवेशन हुआ । गजेन्द्र नारायण सिंह सर्वसम्मति से पार्टी के अध्यक्ष चुन लिए गए । पार्टी अपनी मुख्य मांगों में तराई के सभी मधेसियों को नागरिकता परिचय पत्र दिलाना, हिन्दी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाना, हिन्दी को भी सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में मान्यता, निजामती और सैनिक सेवाओं में मधेसियों के लिए आरक्षण, संघात्मक राज्य प्रणाली की व्यवस्था, मधेसिया की अलग पहचान के साथ राष्ट्रीय मूलधारा में समावेश करने के लिए उसकी भाषा, संस्कृति वेश-भूषा को मान्यता देते हुए जनसंख्या के आधार पर संसद में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के सवालें को मुख्य रूप से उठायी गयी ।

वि.स. २०४८ साल मे हुए आम निर्वाचन मे नेपाल सद्भावना पार्टी को कुछ सफलता मिली । संसदीय कार्यवाही मे इस पार्टी का भूमिका उल्लेखनीय भी रहा । इस के बावजूद भी नेपाल सद्भावना पार्टी अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए विरोध प्रदर्शन, अनशन, मधेस बन्द, मेची- महाकाली रथयात्रा जैसे कार्यक्रम करते रहें । वि.स. २०५१ साल में मध्यावधि निर्वाचन के बाद संसद मे किसी एक पार्टी का बहुमत नही रहा । त्रिशंकु संसद का गठन हुआ और नेपाली राजनीति मे सत्ता निर्माण के लिए सांसदो का खरिद फरोख्त शुरु हुई । एक छोटा, नव गठित, अप्रशिक्षित और कमजोर प्रतिवद्धता के कार्यकर्ताओ से बनी पार्टी होने के कारण से इस संसदीय दौर मे नेपाल सद्भावना पार्टी अपने को बचा न पाया । पार्टी संयुक्त सरकार में सहभागी हुई । इस पार्टी के लोग मंत्री भी बने । सत्ता सुख और सत्ता मोह, सुविधा की राजनीति की परिपूर्ति के लिए पार्टी के नेताओं के बीच गंभीर अन्तरकलह उभर कर आया । इसी

अन्तरकलह के कारण कुछ सांसदों ने पार्टी विभाजन की घोषणा करते हुए राष्ट्रीय समाजवादी जनता दल का गठन किया और सत्ता में भी पहुंचे । यही से नेपाल सद्भावना पार्टी मे विभाजन और विघठन का दुःखद दौर शरु हुआ । पार्टी कमजोर होती गई । एक से बिखर कर कई पार्टीया बनी । मधेसियों के प्रति विभेद, उत्पीडन और शोषण के खिलाफ संघर्ष करने के लिए बनी पार्टी अपने उद्देश्य से विमुख होकर वोट की राजनीति, सत्ता के प्रति समर्पण भाव, भोग-विलास के साधन जुटाने का एक साधन भर रह गया । पार्टी के द्वारा सत्ता राजनीति को ही प्राथमिकता देने के कारण से अवसरवादी नेतृत्व को बढावा मिला, फलतः पार्टी संघर्ष की राजनीति का परित्याग कर नीतिगत रूप से दिशाहीन और विचलित हो गयी । पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष गजेन्द्र नारायण सिंह का दुःखद निधन हुआ । वर्तमान तक की यात्रा मे गजेन्द्र नारायण सिंह और राम जनम तिवारी जैसे नेताओं के द्वारा गठित पार्टी कई दृश्य अदृश्य कारणों से असान्दर्भिक होकर घिसट रहा हैं । बस्तुतः जन्म कालिन उद्देश्यों के आधार पर देखा जाय तो इस पार्टी का पतन हो चुका हैं ।

गणतन्त्र की जननी मधेस : रामराजा प्रसाद सिंह का दौर

देश के पहले गणतन्त्रवादी नेता रामराजा प्रसाद सिंह एक अविचलित और अपने ध्येय के प्रति सम्झौताहीन क्रान्तिकारी थे । सन् ६० मे दिल्ली विश्वविद्यालय का अपना छात्र जीवन के दौरान वे क्यूवा क्रान्ति के उत्प्रेरक चे गुवेरा से प्रभावित हुए । अपने छात्र जीवन से ही उन्होंने नेपाल में जनवादी क्रान्ति और गणतंत्र की स्थापना के लिए छापामार युद्ध के महत्व का आंकलन किया । क्रान्ति के सम्बन्ध में उन का राय था : जिस मुल्क में तत्काल सशस्त्र क्रान्ति की परिस्थिति मौजुद नहीं है, उहाँ के क्रान्तिकारियों को तीन चरणो से गुजरना होगा । पहला, संवैधानिक संघर्ष । दूसरा, अहिंसात्मक क्रान्ति । और तीसरा, सशस्त्र संघर्ष । संवैधानिक संघर्ष को आगे बढाने के लिए वि.सं. २०२८ साल में वे राष्ट्रिय पंचायत मे स्नातक निर्वाचक-क्षेत्र से उम्मेदवार हुए । उन्होने अपना चुनाव घोषणा पत्र में "निर्दलीय संविधान का खात्मा कराना" अपना उद्देश्य बताया था । वे विजयी हुए । निर्वाचन में विजयी होने के बाद भी उन्हें सरकार द्वारा शपथ ग्रहण करने न देकर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया । राजा महेन्द्र ने जेल से रामराजा प्र. सिंह को नारायण हिटी राजदरबार में बुलाकार समझौता करना चाहा, कई तरह के पद, प्रतिष्ठा जैसे प्रलोभन का प्रस्ताव दिया गया । परन्तु राजा महेन्द्र फिर भी असफल ही रहे ।

संवैधानिक संघर्ष के वाद रामराजा प्रसाद सिंह अहिंसात्मक आन्दोलन का तैयारी के लिए मधेस के विभिन्न शहरों, गावों और कस्बों मे आमसभा, जुलूस प्रदर्शन आदि कार्यक्रम को आगे बढाया । उन्हे फिर गिरफ्तार कर करिब ४ वर्ष तक काठमाण्डू के जेल में रखा गया । जेल में ही उन्होंने नेपाल में राजतंत्र के विरूद्ध सशस्त्र क्रान्ति की योजना बनायी । जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने सशस्त्र संघर्ष का तैयारी प्रारम्भ किया । उन्होने एक राजनीतिक संगठन के रूप मे "बहुदलीय जनवादी मोर्चा" गठन कर जनवाद और गणतन्त्र की अवधारणा का सूत्रपात किया । इसी बीच वि.स. २०३७ मे नेपाल मे "पंचायती व्यवस्था वा सुधारिएको पंचायती व्यवस्था" इस बिषय पर जनमत संग्रह का निर्वाचन हुआ था । रामराजा प्रसाद सिंह ने इस निर्वाचन को प्रयोजनहीन और राजा के साथ सम्झौता बताकर बहिष्कार किया । उन का कार्यक्रम सशस्त्र संघर्ष ही था । सशस्त्र संघर्ष की तैयारी के लिए उन्होने सैकडों छापामार तैयार किए । उन का निर्देशन मे जनवादी मोर्चा के तरफ से वि.सं. २०४२ साल आषाढ ६ गते नारायण हिटी राजदरबार, सिंहदरबार, अन्नपूर्ण होटेल लगायत राष्ट्रव्यापी रूप में बम विस्फोट किया गया । बम विस्फोट के माध्यम से राजतंत्र के विरूद्ध संशस्त्र संघर्ष का आह्वान किया गया था ।

संघर्ष का प्रमुख उद्देश्यों मे उन्होने राजतंत्र का अन्त, जनवादी गणतंत्र की स्थापना, निजी सम्पत्ति का उन्मूलन, उपभोग्य सम्पत्तियों में आधारभूत समान अधिकार की मांग को उठाया था । जनवादी मोर्चा के नाम से रामराजा प्रसाद सिंह ने एक वक्तव्य जारी कर "विदेशी आक्रमणकारियों ने नेपाल पर आक्रमण कर युद्ध में नेपाली जनता को पराजित कर पृथ्वीनारायण शाह के नेतृत्व में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की । भावनात्मक रूप से नेपाली राष्ट्रवाद को छिन्न-भिन्न कर विभिन्न जातीयों के गणराज्यों को सैन्य शक्ति के बल से कुचल कर उन्हे दासत्व का जीवन जीने के लिए विवश कर दिया । हमें आजादी,

स्वतंत्रता और आधारभूत अधिकारों से भी वंचित किया गया है । नेपाल और नेपाली जनता के मुक्ति के लिए सशस्त्र क्रान्ति के माध्यम से राजतन्त्र की समाप्ति करना होगा"-कहा था । उस बम काण्ड के आरोप में रामराजा प्रसाद सिंह लगायत के नेताओं को नेपाल के सर्वोच्य अदालत द्वारा फांसी की सजा सुनायी गइ । (इस का विवरण उपर मे दिया गया हैं) इस के बावजूद भी वे लोग भूमिगत रहकर संघर्ष जारी रखे । इस बीच रामराजा प्रसाद सिंह भारत मे निर्वासित जीवन व्यतित कर रहे थें । वि.स. २०४७ मे नेपाल मे बहुदलीय प्रजातन्त्र की स्थापना हुई । रामराजा प्रसाद सिंह इस से सहमत नही थे । भारत सरकार ने उन्हे भारत से कोई कारवाही न करने का कडा हिदायत दिया । नेपाली सरकार के अनुरोध पर जनवादी मोर्चा के नेताओं, कार्यकर्ताओं और छापामारों को गिरफ्तार कर उनके हाथ हथियार जब्त कर लिया गया । वे नेपाल मे हुए वि.स. २०४८ का आम चुनाव मे सहभागी नही हुए । लेकिन वि.स. २०५१ साल का मध्यावधि निर्वाचन में नेपाल जनवादी मोर्चा के ही नाम से भाग लिया । इस आम निर्वाचन मे उन का पार्टी एक भी स्थान नहीं प्राप्त किया । पार्टी की संरचना विखर गयी । जनवादी मोर्चा के कई क्रान्तिकारी लोग माओवादी दल मे सरिक हुए । जैसा कि स्वयं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड ने बताया हैं-माओवादीओं को सब से पहले बम, बारुद और बिस्फोटक बनाने मे प्रशिक्षण देने का काम जनवादी मोर्चा के बिशेषज्ञों ने ही किया था ।

रामराजा प्रसाद सिंह प्रत्यक्षत: मधेस के राजनीति से नही जुडे । परन्तु, मधेसीयों के प्रति हो रहे विभेद से वे परिचित और असहमत थें । रामराजा प्रसाद सिंह का कहना है कि "नेपाल में राजतंत्र का उन्मूलन, जनवादी गणतंत्र की स्थापना और संघात्मक प्रणाली के अन्तरगत मधेसी और विभिन्न जातियों का स्वायत्त शासन कायम होते ही मधेसी और जनजातियों के प्रति कायम भेदभाव और जातीय उत्पीडन का स्वत: अन्त हो जाएगा । क्योंकि पृथ्वीनारायण शाह ने मधेसियों सहित विभिन्न जातियों के गणराज्यों पर सैनिक शक्ति से दमन कर उन्हे खत्म करके उसे पराधीन बनाकर जातीय उत्पीडन और भेदभाव कायम किया था । मधेसी और विभिन्न जातियों का अपना-अपना स्वशासन वाले गणराज्यो की स्थापना के पश्चात् उनके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शोषण एवं उत्पीडन का अंत होने के साथ ही उनकी भाषा, साहित्य, संस्कृति और कला के विकास का समान अवसर प्राप्त होगा ।"

नेपाल मे वि.स. २०६३ के जन आन्दोलन और २०६४ का मधेस आन्दोलन की सफलता के वाद संविधान सभा के द्वारा गणतन्त्र की स्थापना हुई । नेपाली इतिहास का एक अंग के रूप मे रहा २४० बर्ष पुराना शाही राजतन्त्र का अन्त्य हुआ । गणतन्त्र स्थापना के इस मुहीम के ऐतिहासिक आन्दोलन का निर्माण रामराजा प्रसाद सिंह ने किया था । राजतन्त्र के समाप्ति के वाद नेपाल मे संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रपति का पहला चुनाव हुआ । मुल्क का पहला संविधान सभा मे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी प्रथम शक्ति और मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल संविधान सभा का चौथा बडे पार्टी के रूप मे उभरा था । फोरम, तमलोपा और सद्भावा पार्टी मिलकर संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा का गठन किया गया था । देश के इतिहास का पहला राष्ट्रपति निर्वाचन मे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी और संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा (बिशेषत: मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल) के बीच समझदारी हुई थी । इस समझदारी के अनुसार रामराजा प्रसाद सिंह को राष्ट्रपति के उम्मेदवार के रूप मे प्रस्तुत किया गया । परन्तु, यह समझदारी कायम न रहा । राष्ट्रपति निर्वाचन के रोज ही सबेरे एक गंभीर षडयन्त्र के तहत मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले के साथ गोप्य गठबन्धन किया । उपेन्द्र यादव ने अपने पार्टी मे छलफल तक न करके राष्ट्रपति के उम्मेदवार के रूप मे नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले के संयुक्त प्रत्यासी डा. रामवरण यादव को समर्थन किया । मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल मे बडा विवाद हुआ । फोरम नेपाल के तत्कालिन सह अध्यक्ष तथा सभासद् जय प्रकाश प्रसाद गुप्ता ने इस निर्णय को गलत बताते हुए बिरोध किया था । उन्होने इस निर्णय को उपेन्द्र यादव के द्वारा जनक्रान्ति और मधेस बिद्रोह के ललाट पर काला टिका लगाना बताया था । उपेन्द्र यादव का इस राजनीतिक बेइमानी तथा अन्तरघात से अन्य मधेसी पार्टी, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी और सद्भावना पार्टी भी सहमत नही हुआ । फिर भी उपेन्द्र यादव नही माने । राष्ट्रपति का निर्वाचन हुई । मधेसी जन अधिकार फोरम, नेपाल से जय प्रकाश प्रसाद गुप्ता के साथ १४ सभासदों ने राजनीतिक

धर्म का अनुसरण कर रामराजा प्रसाद सिंह के पक्ष मे क्रस मतदान किया । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी और सद्भावना पार्टी ने भी रामराजा प्रसाद सिंह के पक्ष मे मतदान किया । परन्तु, दुर्भाग्य रामराजा प्रसाद सिंह निर्वाचन मे पराजित हुए । डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति बने । रामराजा प्रसाद सिंह के मृत्यू के वाद उन का पार्टी नेकपा एकिकृत माओवादी पार्टी मे विलय करा दिया गया ।

माओवादीओं के द्वारा मधेसी मुक्ति का नारा

नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी (माओवादी) ने वि.स. २०५१ साल से शसस्त्र जनयुद्ध प्रारम्भ किया । जनयुद्ध के दौरान माओवादी ने जातीय और वर्गीय मुक्ति के मुद्दा को जोडतोड के साथ उठाया । क्षेत्रिय, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, भाषिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक समेत हर क्षेत्र में विद्यमान रहा दमन, उत्पीडन से मुक्ति दिलाने का नारा माओवादीओं ने दिया था । नेपाल का बिषेशतः पहाडी क्षेत्रों मे माओवादीओं के इस नारा का गंभीर प्रभाव पडा और लोग जनयुद्ध मे जुटते गयें । मधेस मे भी इस का प्रभाव पडा । परन्तु, माओवादी पार्टी का मधेस मे कमजोर संगठन होने के कारण से शसस्त्र जनयुद्ध का फैलावट सिमित ही रहा था । मधेस मे शसक्त संगठन के बगैर जनयुद्ध को सफलता नही प्राप्त होगा-इस निष्कर्ष के साथ माओवादीओं ने मधेस केन्द्रीत "मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा" का गठन प्रस्ताव को आगे बढाया । माओवादी पार्टी मे उस वक्त मातृका यादव, जयकृष्ण गोइत, प्रभु साह, सत्यनारायण भगत, महेन्द्र पासवान, भरत साह, विनोद उपाध्याय, अशोक जयसवाल, कृष्ण देव सिंह दनुवार, राम कुमारी यादव, रामचन्द्र मण्डल, शिवचन्द्र कुशवाहा आदि कद्दावर नेता थे । माओवादी पार्टी के निर्देशन पर भूमिगत अवस्था मे ही वि.स. २०५७ साल भाद्र २५ गते एक छलफल कार्यक्रम रखा गया और "मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोचा" का नामाकरण कर इस का गठन करने का निर्णय लिया गया । महेन्द्र पासवान के संयोजकत्व मे एक तयारी समिति बनी थी । "मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा" का पहला संस्थापक अध्यक्ष जयकृण गोइत बनाए गए । अपने स्थापना कालिन उद्देश्य मे मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा ने उल्लेख किया था : "मधेसी समुदाय के ऊपर युगों से कायम विभेद और शोषण से मुक्ति दिलाना हैं । इसके लिए मधेसी समुदाय को आत्मनिर्णय और स्वायत्त शासन का अधिकार दिया जाएगा । देश को सामन्तवाद, विस्तारवाद (भारतीय), साम्राज्यवाद से मुक्ति दिलाने के लिए ने.क.पा. (माओवादी) द्वारा संचालित जनयुद्ध मे सरिक रहेंगें ।" नेपाल में नयी जनवादी क्रान्ति को समर्थन करना और जनवादी गणतंत्र स्थापना करने के लिए अग्रसर होना मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा का उद्देश्य बताया गया था ।

नव गठित मोर्चा और अध्यक्ष जयकृष्ण गोइत का संघर्षशील व्यक्तित्व और कुशल संगठनात्मक कार्य के बदौलत मोर्चा अल्प समय मे ही एक शसक्त संगठन मे रूपान्तरित हुआ । माओवादी दस्तावेज के अनुसार वि.स. २०५८ साल भाद्र ५ गते भूमिगत रूप मे सर्लाही जिला का किसी भाग मे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल "प्रचण्ड" के द्वारा मोर्चा का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन का उदघाटन किया गया था । उदघाटन समारोह का अध्यक्षता जयकृष्ण गोइत ने किया था । इस मौके पर माओवादी के पूर्वाञ्चल उपब्यूरो के सदस्य रहे उपेन्द्र यादव भी उपस्थित थे । यही प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन से मोर्चा का संस्थापक अध्यक्ष जयकृष्ण गोइत को दर किनार कर मातृका यादव को अध्यक्ष बनाया गया । उपाध्यक्ष मे क्रमशः महेन्द्र पासवान, सत्यनारायण भगत और विनोद उपाध्याय थें । प्रभु साह महासचिव बनाए गए । यहीं से माओवादी के अध्यक्ष प्रचण्ड और जयकृष्ण गोइत के बीच मत भिन्नता उभर कर आया । माओवादी पार्टी मे मधेस की मुक्ति के सवाल पर मोर्चा से प्रचण्ड सिर्फ प्रचारात्मक भूमिका चाहते थें जब की जयकृष्ण गोइत मधेस की मुक्ति के सवाल पर माओवादी पार्टी का स्पष्ट दृष्टिकोण और ठोस कार्यक्रम चाहते थें । प्रचण्ड को गोइत का भूमिका और दो टूक दृष्टिकोण रास नही आ रहा था । जयकृष्ण गोइत को दर किनार करने के लिए ही मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन अयोजन किया गया था । इस सम्मेलन मे प्रचण्ड ने अपने मुँहबोले मधेसी नेताओं के बल पर मातृका यादव को मोर्चा का अध्यक्ष बनाया । यही से जयकृष्ण गोइत को किनारा किया गया । उन्हे मधेस के संगठन से दूर कर संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद का पूर्वाञ्चल संगठन मे धकेल दिया गया । यहाँ गौर करने की बात यह भी हैं की वाद के दिनों मे मातृका यादव भी प्रचण्ड नेतृत्व के माओवादी पार्टी मे नही रह सकें । जयकृष्ण गोइत भी माओवादी परित्याग कर मधेस की मुक्ति के लिए शसस्त्र संघर्ष का रास्ता

को अपनाया । इन सभी घटनाक्रमों बावजूद माओवादी जनयुद्ध मे लगकर मधेस की मुक्ति का चाह मे सयकडौं होनहार मधेसी क्रान्तिकरियों ने अपना जीवन को शहादत दिया, शहीद हुए, मारे गये । धनुषा निवासी रामबृक्ष यादव बहुत बडे नेता थें । वे मारे गयें । उन का पुत्र शेखर, दामाद डम्बर की हत्या हुई । धनुषा के ही रामचन्द्र मण्डल मारे गए । सिरहा के देवनारायण यादव और उन का सुपुत्र सुजित नारायण यादव का एक साथ निर्ममता पूर्वक हत्या किया गया । सिरहा मे ही जीतलाल यादव, मोहन सदा, धनपैत महत्तो, योगेन्द्र मण्डल, महेन्द्र साफी, लक्ष्मण मुखिया, राम किशन यादव, शिव यादव, प्यारे खाँ, राज कुमार यादव, देवलाल यादव, आनन्द कुमार यादव, फेकन यादव, राम नारायण यादव, लरिया यादव, सोनिलाल मोची, सितलाल यादव, म. नेजाम खाँ, सरिता कुमारी महत्तो, राम जुलुम यादव, बलराम यादव, लक्ष्मण पैत मण्डल, वैद्यनाथ यादव, कारी मण्डल, सीताराम यादव, देवेन्द्र प्रसाद सिंह, सोनेलाल मण्डल, महेन्द्र महत्तो आदि पचासों मारे गए । सप्तरी मे अजवलाल यादव की हत्या हुई । मनरुप महतो, पसिन्द्र पटेल, लालबाबू पासवान, हनुमान झा, गोलहीया देवी पासवान, राज कुमार यादव, कारी साह, फुलगेन राम, प्रदित दास, राम सेवक ठाकुर, रामनारायण सदा, महेन्द्र साह, रुदल राइन, राम उदगार कापड आदि मारे गये । माओवादीयों और स्वयं मधेसी मुक्ति मोर्चा के लागों ने भी सयौं के संख्या मे निपराध मधेसीयों का भी हत्या किया । यहाँ उन सभी विवरणों को उजागर करने का उद्देश्य नही हैं । सिर्फ यह अनुरोध किया जाता हैं कि, मधेस के मुक्ति के लिए माओवादी पार्टी मे रहकर भी कयौं मधेसी ने शहादत दिया, जिस से आज स्वयं प्रचण्ड और बैद्य जी के नेतृत्व मे रहा माओवादी पार्टीया अज्ञानी बना हुआ हैं ।

मधेस विद्रोह और सत्ता समर्पण-मुद्दा विसर्जन का दौर

मधेसी जन अधिकार फोरम, नेपाल का जन्म उस वक्त हुआ जब एक बार फिर मधेस की राजनीतिक आन्दोलन शिथिल हो चुका था । नेपाल सद्भावना पार्टी कई टुक्रो मे बिखर गई थी । माओवादीयों ने उपेक्षित, उत्पीडित क्षेत्र एवं समुदाय का मुक्ति के सवाल को जोर से उठाया था । पहाडी क्षेत्रों मे जातीय मुक्ति का सवाल सर्वत्र उठना शुरु हुआ था । उस समय वि.स. २०५४ साल मे विराटनगर मे रह रहे उपेन्द्र यादव, पत्रकार रामरिझन यादव, शिक्षक जुगेस्वर मेहत्ता और कलेज प्रध्यापक राजेन्द्र प्रसाद साह आदि ने बहस, छलफल, अन्तरक्रिया, विचार गोष्ठी के माध्यम से मधेसी समुदाय का समस्याओं को उजागर करने लिए फोरम का अवधारणा को आगे बढाया । फोरम का गठन पूर्व के प्रारम्भिक दौर मे उपेन्द्र यादव ने महन्थ ठाकुर, आर.डी. आजाद, खुशीलाल मण्डल, जय प्रकाश प्रसाद गुप्ता, जयकृष्ण गोइत, जीतेन्द्र नारायण देव, डा. महानन्द ठाकुर, महादेव साह, राजेस्वर नेपाली, भाग्यनाथ गुप्ता जैसे लोगों से बहद् परामर्श किया था । इन सभी लोगों के सहयोग से इस की गठन को बढावा मिला । व्यक्तिगत तौर पर उपेन्द्र यादव वामपंथी नेता सहना प्रधान और मनमोहन अधिकारी के नेतृत्व मे रहा तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) से सम्बन्ध रखते थे । वि.स. २०४७ साल के जन आन्दोलन से ठिक पहले इस कम्युनिष्ट घटकका विलय नेकपा (माले) मे होकर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले बनने के बाद वे एमाले पार्टी के तरफ से सुनसरी संसदीय क्षेत्र नं. ४ से उम्मेदवार थे । नेपाली कांग्रेस के बडे ख्याति प्राप्त नेता डा. खलिल आजाद से पराजित हो उन की जमानत जफ्त हुआ । एमाले के भीतर की गुटवन्दी से परेशान उपेन्द्र यादव तब गजेन्द्र नारायण सिंह के नजदिक पहुंचे, जहाँ वे मधेस की समस्याओं से ज्यादा परिचित हुए । गजेन्द्र नारायण सिंह से प्रभावित उपेन्द्र यादव नेपाल सद्भावना पार्टी मे सहयोगी की भूमिका मे सरिक हुए और उस पार्टी का विराटनगर मे हुआ राष्ट्रिय महाधिवेशन मे सहभागी थें । बिभिन्न कारणों से सद्भावना पार्टी उन्हे रास नही आया और उसी समय माओवादी पार्टी से सम्बन्धित और विराटनगर क्षेत्र मे जातीय मोर्चाओं को संगठित करने हेतू कार्यरत् सुरेश आले मगर से उन का परिचय हुआ । यही से वे माओवादी के निकट पहुंचे । और, मधेस मे माओवादी पार्टी का संगठन विस्तार करने का माओवादी रणनीति के तहत फोरम नेपाल को माओवादी संगठन से जोडा । माओवादी नेता मोहन बैद्य किरण उस समय पूवार्ञ्चल के इंचार्ज थे । उपेन्द्र यादव मोहन बैद्य से माओवादी शिक्षा मे दीक्षित और संगठित हुए । अब फोरम नेपाल अदृश्य रूप में माओवादीओं का ही एक अंग बना । उपेन्द्र यादव का एक हि समय तीन पार्टी एमाले, सद्भावना और माओवादी से ताल्लुकात को एमाले पचा नही

पाया । उन के खिलाफ अनुशासन की कारवाही चलाया गया । फिर भी उपेन्द्र वास्तविकता को छुपाए हुए एमाले मे भी आते जाते रहें । एमाले पार्टी का नेपालगञ्ज महाधिवेशन के समय स्वयं का घोर उपेक्षा किए जाने से उन्होने एमाले का परित्याग किया । इस के वाद उपेन्द्र यादव जातीय राजनीति मे लगे और गोपाल सेवा समिति (यादव समुदाय का जातीय संगठन) के मोरंग जिला कार्य समिति के अध्यक्ष बने । रामरिझन यादव सचिव थें । दृश्य-अदृश्य घटनाओं का आरोह अवरोह मे वि.स. २०५४ साल मे उपेन्द्र यादव का अगला कार्य स्थल मधेसी जन अधिकार फोरम, नेपाल बना । जिसका जिक्र अपर किया गया हैं ।

अब वे पूर्णकालिन माओवादी कार्यकर्ता थें । माओवादी संलग्नता के आरोप मे उपेन्द्र यादव भूमिगत हए और फिर भारत मे रहने लगें । तत्कालिन कांग्रेसी प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के समय मे माओवादी के साथ सरकार की वार्ता प्रारम्भ हुई । उपेन्द्र यादव नेपाल आए । सप्तरी के मधेसी नेता आर.डी. आजाद फोरम के महासचिव थें । वि.स. २०५९ मे विराटनगर मे मधेसी जन अधिकार फोरम, नेपाल का पहला महाअधिवेशन हुआ जिसके प्रमुख अतिथी रामराजा प्रसाद सिंह थें । इस महाअधिवेशन का सम्पूर्ण खर्च माओवादी पार्टी ने जुटाया था और माओवादी के केन्द्रीय नेता कुमार पौडेल अधिवेशन मे माओवादी पार्टी के तरफ से औपचारिक ईंचार्ज के रूप मे उपस्थित थें । जेल से रिहा होने के बाद नेपाली कांग्रेस को परित्याग कर जय प्रकाश प्रसाद गुप्ता इस अधिवेशन मे सरिक हुए थें । दो दिवसीय इस महाअधिवेशन का दुसरा दिन ही सरकार-माओवादी शांतिवार्ता भंग हुई और देश मे संक्रमण काल की घोषणा हुई । उपेन्द्र यादव अधिवेशन स्थल से ही भूमिगत हो फिर भारत चले गए । अब फोरम नेपाल का नेतृत्व जय प्रकाश गुप्ता ने सम्हाला । उपेन्द्र यादव का भारत प्रवास के दौरान ही जय प्रकाश गुप्ता विहार प्रान्त के कटिहार मे हूई बैठक से फोरम नेपाल के महासचिव और फिर सह अध्यक्ष बनाए गए । वि.स. २०६३ के जन आन्दोलन के वाद उपेन्द्र यादव भारत प्रवास से २०६४ साल बैशाख २० गते नेपाल वापस आये । इस वक्त तक मधेसी जन अधिकार फोरम, नेपाल का संगठन का अपेक्षित विकास हो चुका था ।

मधेसी जन अधिकार फोरम, नेपालको संयोगवश वि.स. २०६३ साल मे हुए पहला मधेस विद्रोह मे नेतृत्व का श्रेय प्राप्त हुआ । वि.स. २०६४ का संविधान सभा के निर्वाचन मे फोरम नेपाल संसद और संविधान सभा मे चौथा बडा शक्ति के रूप मे उभरा । परन्तु, कुछ ही समय के वाद यह पार्टी भी नेपाल सद्भावना पार्टी के तरह ही मधेसियों के प्रति विभेद, उत्पीडन और शोषण के खिलाफ संघर्ष करने के बजाय अपने उद्देश्य से विमुख होकर वोट की जातिवादी राजनीति, स्वयं उपेन्द्र यादव का सत्ता के प्रति अन्ध आशक्ति और उन के द्वारा ही गुटबन्दी का सिर्जना, मधेस की मुद्दाओं का परित्याग, पार्टी संगठन को निजी भोग-विलास के साधन जुटाने का माध्यम मे रूपान्तरित करना-इस प्रकार की कार्यो को प्राथमिकता देने से आज यह पार्टी नीतिगत रूप से दिशाहीन और विचलित हो गयी हैं । पहली संविधान सभा मे ५३ स्थान प्राप्त यह पार्टी वि.स. २०७० मे सम्पन्न संविधान सभा का दुसरा निर्वाचन मे सिर्फ १२ स्थान ही सुरक्षित कर पाया । अल्प समय मे बारम्बार विभाजित यह पार्टी आज भी बिभाजन का भय झेल रहा हैं । मधेसी जन अधिकार फोरम, नेपाल अब मधेस के विभिन्न जात/जाति, भाषा-भाषी, वर्ग, धर्म, विचारधारा एवं विभिन्न सिद्धान्तों में आस्था रखनेवाले मधेसियों जो इस पार्टी के नीति, सिद्धान्त एवं कार्यक्रम तथा उद्देश्यों का समर्थन करता रहा हैं-यह पार्टी अब उन मधेसीयों का साझा संगठन नही रहा ।

संघर्ष सारथि का नाम : तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान

अनेकन् आरोह-अवरोह के बावजूद मधेस का संघर्ष फिर भी नही रुका हैं । मधेसी समुदाय को अधिकार सम्पन्न करने का क्रान्तिकारी अभिभारा अब तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान ने वहन किया हैं । अभियान का गठन वि.स. २०६९ साल का चैत्र ६ गते हुआ । इस का घोषणा केन्द्रीय संयोजक जय प्रकाश गुप्ता ने राजधानी काठमाण्डौं का डिल्लीबजार स्थित नेपाल साँस्कृतिक संघ मे मधेसीयों का एक सभा के बीच किया । जय प्रकाश गुप्ता इस के एक रोज पहले ही १४ माह का कारावास से रिहा हुए थे । अभियान के घोषणा सभा के दौरान कहा गया : तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान एक क्रान्तिकारी संगठन होगा । यह सत्ता की राजनीति से दूर रह एक शसक्त क्रान्तिकारी संगठन का निर्माण कर मधेस की अधिकारों की प्राप्ति हेतू आन्दोलन का तैयारी करेगी । यह अभियान मधेसी जनता का, दलित का, आदिवासी-जनजाति

एवं थारू समुदाय का, पहाड के राज्य रुपान्तरण के पक्षधर लोगों का, पहाड की जनजाति और देश भर के मुसलमानों का साझा मंच होगा । देशवासी से अपील मे अभियान ने अनुरोध किया कि, देशभर में रह रहे हमारे मित्र, शुभ चिन्तक-जो कल किसी भी पार्टी मे आबद्ध थे "अब हम तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान के अंग बने, इसमें संगठित और समूहकृत होकर आन्दोलन को बढावें ।" अभियान ने मधेस के सशस्त्र संगठनों को अनुरोध किया "अब हथियार की राजनिति का छोडे, नेपाल से अलग स्वतन्त्र देश बनाने वाली सोच का परित्याग कर शान्तिपूर्ण राजनीति की मूल धारा में समाहित हों ।" अभियान ने स्पष्ट किया कि, मधेस की राजनीति का निर्धारण एक चुनाव नहीं करेगा । कुछ लोगों को सरकार मे मंत्री होने से नही होगा । तराई-मधेस की अधिकार की यह लडाई बहुत लम्बी चलेगी । यसर्थ, भावी क्रान्ति के लिये एक क्रान्तिकारी चरित्र की पार्टी चाहिये । 'यदि आप के मन में क्रान्ति की भावना है, यदि आप के मन में आमूल परिवर्तन की इच्छा है, आप ने युग परिवर्तन करना चाहा है, आप ने स्थापित पुरानी मान्यताओं को बदलना चाहा है तो क्रान्ति की सिर्फ बातें करने से नही होगी, उसके लिये एक क्रान्तिकारी पार्टी की निर्माण की आवश्यक्ता है । सामान्य सुधारवादी, विकास और सामाजिक सुधार की बातें करने बाली पार्टीयों से आमूल राजनीतिक परिवर्तन नहीं हो सकता । राज्य का शासकीय स्वरुप परिवर्तन नहीं हो सकता । नेपाल की स्थापित स्थायी सत्ता-जिसने एक जाति के राज्य, जिसने एक स्वार्थ के साम्राज्य को कायम किया है, उसे बदल नहीं सकते । इस देश में एक स्थायी सत्ता है । यह स्थायी सत्ता एक निश्चित समुदायका है । शासन मे उसके अनवरत वर्चस्व को कायम रखने वाले उस समुदायका जो स्थायी सत्ता है, उस सत्ताको हम बदल सके तभी हमारा संघर्ष विजयी माना जाएगा । इस देश में विद्यमान स्थायी सत्ता के रूपान्तरण के लिये संघर्ष को आगे बढाना होगा ।

तमरा अभियान का मानना है कि, विद्यमान मधेस की राजनीति को देखते हुए अब हमें उपयोगी एवं अनुपयोगी धारा का रेखांकन करना होगा । मधेस आन्दोलन से जुडे हुएं युवाओं को मुद्दा के आधार पर आन्दोलन का समीक्षा करना होगा । मधेसी नेतागण-जो विभिन्न समय सत्ता में रहे और आज भी सत्ता से परिवर्तन होने का वकालत कर रहे हैं, उन्होंने क्या हासिल किया ? इस का मूल्यांकन करना होगा । मूल्यांकन प्रणाली की अभाव मे मधेसी नेताओं का उन के कथनी और करनी का हम समुचित मूल्यांकन नहीं कर पा रहे है । इसी लिये हम सत्ता के दलालो को, नेपाली राज्य सत्ता के घुसपैठिए को भी क्रान्तिकारी मानने का महाभूल कर बैठते हैं । मधेसी मुक्ति अभियान को बहुत ज्यादा नोक्सानी पहुंचाने बाले, सत्ता में समर्पित होने वालों, मुद्दा का विसर्जन करने वालों को भी हम प्रगतिशील मानने की गलती करते रहे है । इसलिये यदि अब भी हमने क्रान्तिकारी धार नही खींची और क्रान्तिकारी आधार का निर्माण नही किया तो हम फिर भूलभुलैया में पडेंगे । अतः मधेस की राजनिति में एक स्पष्ट विभाजन रेखा बनानी होगी । मधेस का यथास्थितिवादी पक्ष कौन कौन है ? किस पक्ष ने सत्ता के लिये अपना मुद्दा छोडा है ? और मधेस का अग्रगमनकारी-पक्ष कौन-कौन है ? जब मधेसी नेताओं ने घुटने टेके, किस पक्ष ने उसका विरोध किया है ? इस दुसरा पक्ष का समुहकृत रूप ही तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान का धार है । अब के मधेस आन्दोलन का आधार स्तम्भ है । इसका पहचान करना होगा । इसी अभिप्राय से तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान का जन्म हुआ हैं ।

अब हमें नयी सोच, साहस और शक्ति के साथ आगे बढना है । अब मधेस की पुरानी परिभाषा से काम चलने की स्थिति नहीं है । मधेस सिर्फ एक जात या समुदाय के बसोबास का स्थान नहीं है । हम अब यह भी नही सोच सकते हैं कि सिर्फ 'हम ही मधेस में रहेंगे और पर्वतीय समुदाय के भाईयों का मधेसी भूमी मे इसमें स्थान नहीं है । 'मधेस अन्य समुदाय के लोगों का बसोबास का स्थान नहीं होगा' ऐसी सोच सही नहीं है । मधेस की सही परिभाषा भी यह नहीं है । हम मधेस को इस रूप मे परिभाषित करना चाहते हैं कि आज का मधेस, संघीय नेपाल के एकल जातीय पहिचान का मधेस नहीं होगा । आज के संघीय नेपाल के मधेस में 'मधेसी समुदाय' के नाम से हम जिसे पहचानते हैं-सिर्फ इनके बसोबास का मधेस मात्र मधेस नहीं है । मधेस एक सामुहिक बसोबास का स्थान है । अर्थात मधेस धार्मिक अल्पसंख्यक मुसलमानों के बसोबास का स्थान भी है । मधेस आदिवासी थारू के आदिकाल से बसोबास का स्थान भी है । इसलिये आज जब हम मधेस की बात करते हैं, हम ऐसे प्रदेश की परिकल्पना जहां राजनीतिक

अग्राधिकार सिर्फ मधेसी समुदाय का हो, जहां मधेसी प्रथम श्रेणी के नागरिक हों और पर्वते समुदाय के भाईयों को दूसरा श्रेणी हो-ऐसे मधेस की परिकल्पना हम नहीं कर रहे हैं ।

ऐसा कहते हुए हम पर्वते समुदाय के भाइयों से एक निवेदन भी करते हैं । आज तक आप राज्य व्यवस्था से विभेद का शिकार नहीं हुए हैं । पर्वते समुदाय भौगोलिक-आर्थिक कारणों से उपेक्षा के शिकार हुए हैं । पर्वते समुदाय के लोगों को भौगोलिक रूप से दूरुह और कठिन जीवन भोगने का सयौं वर्ष का दु:खद अतित होगा, परन्तु एक सामुदायिक कारण से, रूप-रंग के कारण से पर्वते समुदाय के लोग राज्य विभेद का शिकार नही हुए हैं । पर्वते समुदाय राज्य द्वारा उसके भाषा के कारण, उसके वेश भूषा के कारण या उसके पहचान के कारण बहिष्करण में नही पडे है । पर्वते समुदाय से हमारा यही आग्रह है कि, हम इतिहासकाल से ही भोगते आए इस सत्यको, जो हमने हमारे भाषा के नाम में भोगा, हमने हमारे वेशभूषा के नाम पर भोगा, हमारे सामुदायिक पहचान के कारण हम भोगते आए है-यदि पर्वते समुदाय के भाइ बन्धु इस व्यवहार की समाप्ति के लिये हमारे साथ सहकार्य करना चाहें, यदि हम हाथ में हाथ डालकर चलना चाहें तो, देश की समुन्नति और सदभाव का इससे बडा उदाहरण भविष्य के नेपाल में और कोई नहीं होगा । तमरा अभियान को अब एक नयां विचार, नयां संकल्प-जिससे समस्या को बढाना नही है, जिससे समाज और देश में विभाजन को बढावा मिले, वल्कि सामञ्जस्यता के आधार में समाधान खोजना है, विचारों को एकाकार करके नये वैचारिक अभियान को आगे बढाने का संकल्प अभियान ने लिया हैं ।

तराई मधेस राष्ट्रिय अभियान आज तक नेपाल मे राणा शासन से मुक्ति और प्रजातन्त्र के लिए, संसदीय लोकतन्त्र के लिए, पंचायति व्यवस्था के दौरान राजाओं के तानाशाही से देश को मुक्त कराने के लिए, गणतन्त्र और संघीयता के स्थापना के लिए हुए सभी ऐतिहासिक संघर्षो मे बलिदान देने बाले सम्पूर्ण मधेसी समुदाय के लडाकु योद्धाओं का सपना पुरा करने का अब का संघर्ष का नाम हैं ।

oo oo

Please Visit
www.jayprakashgupta.com
www.facebook.com/jayprakash.gupta.735
www.jpguptablog.wordpress.com
Email: jpananda@gmail.com